RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

INDORE 02 SEPTEMBER TO 08 SEPTEMBER 2020 प्रति बुधवार वर्ष 06 अंक 2 पृष्ठ 8 कीमत 5 रु.

Inside News

चीन की जगह लोकल सप्लायर्स से कच्चा माल खरीद रहीं FMCG कंपनियां Page 2

लॉकडाउन नियमों में राहत का खुदरा विक्रेताओं के संघ ने किया स्वागत Page 3

अगस्त में जम कर बिकीं कारें मारुति की बिक्री 17% से ज्यादा बढ़ी Page 7

editoria!

जीडीपीः सुरंग और रोशनी

सोमवार को जारी मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही के जीडीपी आंकड़ों ने किसी खुशफहमी के लिए गुंजाइश नहीं छोड़ी है। सबको पता था कि आंकड़े गिरावट वाले होंगे लेकिन गिरावट 23.9 फीसदी की हो जाएगी, यह शायद ही किसी ने सोचा होगा। निश्चित रूप से ये आंकड़े गंभीर हैं, लेकिन जीडीपी में गिरावट का गवाह बनने वाले हम कोई इकलौती अर्थव्यवस्था नहीं हैं। कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन लगभग सारे देश विकास दर में अच्छी-खासी गिरावट का सामना कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि खराब आंकड़ों के पीछे सीधे तौर पर यह वजह काम कर रही है कि इस तिमाही के दौरान 68 दिन से भी ज्यादा समय तक देशव्यापी लॉकडाउन लागू रहा, जिसमें तमाम आर्थिक गतिविधियां करीब-करीब ठप हो गई थीं। अकेला कृषि क्षेत्र इससे मुक्त रहा। नतीजा यह कि जहां तमाम सेक्टर गिरावट दिखा रहे हैं वहीं कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस तिमाही इसमें 3.4 फीसदी की वृद्धि हुई जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई थी। सवाल है कि अकेले कृषि क्षेत्र की बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था को कितना सहारा दे पाएगी। इसी से जुड़ा दूसरा सवाल यह है कि इस भीषण गिरावट से उबरने की क्या सूरत हो सकती है। इन दोनों सवालों का जवाब खोजने के सूत्र हमें इस एक तथ्य में मिलते हैं कि इस गिरावट को विशुद्ध आर्थिक परिघटना नहीं माना जा सकता। इसके पीछे लॉकडाउन का वह फैसला है जो कोरोना वायरस से बचाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। इस आपदा का तात्कालिक और अस्थायी चरित्र हमारी उम्मीद का सबसे बड़ा आधार है। कहा जा सकता है कि जैसे-जैसे लॉकडाउन की बंदिशें हटेंगी वैसे-वैसे अर्थव्यवस्था की सेहत दुरुस्त होती जाएगी। हालांकि मामला इतना आसान भी नहीं है। ध्यान रखना होगा कि इस दौरान यानी अप्रैल से जून की अवधि में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर (पीएफसीई) के आंकड़े 54.3 फीसदी गिर गए जबकि पिछले साल की इसी अवधि में इसमें 56.4 फीसदी की बढ़त हुई थी। पीएफसीई परिवारों की खपत आंकने का सटीक पैमाना माना जाता है। लॉकडाउन ने अगर उनके कार या टीवी खरीदने के फैसले को प्रभावित किया है तो इसकी वजह सिर्फ मौजूदा संकट नहीं है। किसी भी परिवार में ऐसे फैसले भविष्य की निश्चितता या अनिश्चितता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। यानी जरूरत सिर्फ यह नहीं है कि जिन भी क्षेत्रों को खोला जा सकता है उन्हें जल्द से जल्द खोला जाए। जरूरत यह भी है कि मजदूरों-कर्मचारियों के काम और उनके वेतन की गारंटी की जाए और उनमें यह भरोसा कायम किया जाए कि उनकी नौकरी आगे भी बची रहेगी। ज्यादातर दफ्तरों-कारखानों को बंद होने से रोका जा सका तो बाजार का संकुचन ज्यादा नहीं खिंचेगा और भारत लंबी मंदी का शिकार होने से बच जाएगा। जाहिर है, देश के सामने संकट बहुत बड़ा है, लेकिन एक अच्छी बात भी है कि सुरंग के दूसरे छोर से रोशनी की किरणें दिखनी बंद नहीं हुई हैं।

इंदौर में सीपेट का सेंटर स्थापित करने के लिए मिली सहमति

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

प्रदेश में औद्योगिक सुविधाओं को बढाने के लिए प्लास्टिक उद्योग द्वारा लम्बे समय से इँदौर में सीपेट का सेंटर खोलने की मांग की जा रही है। इस दिशा में सोमवार को इंडियन प्लास्ट पैक फोरम के प्रतिनिधि मंडल सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विभाग के मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा से मिला। उन्होनें तत्काल सीपैट सेंटर की इंदौर में स्थापना करने की जरूरत को स्वीकार किया और 10 एकड लैंड के लिए सैद्धांतिक सहमति प्रदान की। उन्होनों प्रतिनिधि मंडल से विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा।

प्रदेश के एमएसएमई मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा के इंदौर प्रवास के दौरान रेसिडेंसी कोठी में इंडियन प्लास्ट पैक फोरम के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस दौरान इंदौर में CIPET सेंटर खोलने हेतु जमीन का आवंटन के लिए निवेदन किया। इसकी आवश्यकता और उपयोग को जान कर मंत्री श्री सखलेचा ने जमीन उपलब्ध करवाने की बात मांग मान ली। साथ ही इसे निर्माण और स्थापना से संबधित अन्य जानकारी के साथ विस्तृत रिपोर्ट देने की बात कही। जिसे जल्दी ही आईपीपीएफ द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। प्रतिनिधी मंडल में आईपीपीएफ अध्यक्ष श्री सचिन बंसल, सचिव श्री राम किशोर राठी, कोषाध्यक्ष श्री विकास बांगड भी मौजूद थे।

■ एमएसएमई मंत्री सखलेचा से मिला आईपीपीएफ का प्रतिनिधी मंडल ■ शहर को औद्योगिक क्षेत्र में मिलेगी नई सौगात

एसोसिएशन अध्यक्ष श्री सचिन बंसल ने बताया कि प्लास्टिक उद्योगों के लिए Central Institute of Plastics Engineering and Technology का सेंटर वर्तमान में मप्र में मात्र भोपाल और ग्वालियर में है। ऐसे में किसी भी उत्पाद की प्रमाणिकता के लिए वही जाना होता है। इंदौर में सेंटर की स्थापना होने पर उद्योगों को सुविधा के साथ ही युवाओं को रोजगार देने वाले कोर्स प्रारंभ हो सकेगें और प्रदेश में नए अवसर मिलेगें। इस सेंटर को पब्लिक प्राइवेट मॉडल के रूप में संचालन किया जाएगा। उन्होनें बताया कि इस दिशा में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल डिपाटमेंट के द्वारा पहले ही अपनी स्वीकृति जा चुकी है और इस संबध में प्रमुख सचिव इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट पॉलिसी को पत्र भी लिखा जा चुका है ।

लगातार दूसरे कारोबारी दिन बढ़त पर बंद हुआ बाजार

सेंसेक्स ने पार किया 39000 का आंकड़ा

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 0.48 फीसदी की बढ़त के साथ 185.23 अंक ऊपर 39086.03 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.63 फीसदी ऊपर 62.50 अंकों की बढ़त के साथ 11542.75 के स्तर पर बंद हुआ।

ऐसा रहा दिग्गज शेयरों का हाल

दिग्गज शेयरों की बात करें, तो आज जी लिमिटेड, एम एंड एम, टाटा मोटर्स, इंफ्राटेल और अडाणी पोर्ट्स के शेयर हरे निशान पर बंद हुए। वहीं बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी और नेस्ले इंडिया के शेयर लाल निशान पर बंद हुए।

सेक्टोरियल इंडेक्स पर नजर

सेक्टोरियल इंडेक्स पर नजर डालें, तो आज पीएसयू बैंक और फाइनेंस सर्विस के अतिरिक्त सभी सेक्टर्स हरे निशान पर बंद हुए। इनमें आईटी, प्राइवेट बैंक, मेटल, एफएमसीजी, ऑटो, फार्मा, रियल्टी मीडिया और बैंक शामिल हैं।

हरे निशान पर खुला था बाजार

शेयर बाजार की शुरुआत बढ़त पर हुई थी। सेंसेक्स 60.38 अंक यानी 0.16 फीसदी ऊपर 38961.18 के स्तर पर खुला था और निफ्टी 0.07 फीसदी यानी 8.30 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 11478.55 के स्तर पर खुला था।

पिछले कारोबारी दिन बढ़त पर बंद हुआ था बाजार

पिछले कारोबारी दिन शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ था। सेंसेक्स 0.71 फीसदी की बढ़त के साथ 272.51 अंक ऊपर 38900.80 के स्तर पर बंद हुआ था और निफ्टी 0.73 फीसदी ऊपर 82.75 अंकों की बढ़त के साथ 11470.25 के स्तर पर बंद हुआ था।

वेंचर कैटालिस्ट्स के एसेलरेटर फंड, 9यूनिकॉर्न्स ने 100 करोड़ रुपए का पहला फंड हासिल किया

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

वाई कॉम्बिनेटर की शुरुआती दिनों की नीति की तर्ज पर बनाए गए, भारत के 9यूनिकॉर्न एसेलरेटर फंड 9यूनिकॉर्न्स ने 100 करोड़ रुपये 14 मिलियन डॉलर का अपना पहला फंड हासिल करने की घोषणा की है। इस फंड का निवेश 100 से अधिक शुरुआती चरण के स्टार्ट-अप्स में किया जाएगा, जिसका लक्ष्य लाभकारी स्टार्ट-अप्स की जल्दी पहचान करके उन में पहले निवेश करना होगा। 9 यूनिकॉर्न्स की स्थापना वेंचर कैटालिस्ट्स वीकैट्स के संस्थापकों - डॉ. अपूर्व रंजन शर्मा, अनुज गोलेचा, अनिल जैन और गौरव जैन ने की है। वे भारत में 75 से अधिक घरेलू स्टार्ट अप्स के पोर्टफोलियो में से 30ह्र मल्टी-बैगर्स के एक अनूठे ट्रैक रिकॉर्ड को पहले ही उजागर कर चुके हैं, जिसमें भारतपे, बियरडो, पीसेफ और फाइंड जैसे स्टार्ट-अप शामिलहैं, जिनमें वीकैट्स एक शुरुआती स्तर का निवेशक था। सॉफ्टबैंक समर्थित ओयो रूम्स में भी एक एंजेल निवेश रह चुके, डॉ. अपूर्व रंजन शर्मा ने एक बयान में कहा कि, 'भारतीय उद्यमियों पर दांव लगाने का आज से ज़्यादा कोई बेहतर समय नहीं है। हम ऐसे स्टार्ट-अप्स में उछाल देख रहे हैं जो भारत के विभिन्न हिस्सों में पैदा हुई भारतीय और वैश्विक समस्याओं को हल करने पर केन्द्रित रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि भारत में यूनिकॉर्न की संख्या 4 गुना बढ़ जाएगी, जिनकी संख्या आज 36 है, वे आगे चलकर 140 हो जाएंगे।' भारत में, पहले दौर का फंड हासिल करने के लिए अधिकांश स्टार्ट-अप संघर्ष करते हैं। वे पूंजी के लिए ज्यादातर दोस्तों और परिवार पर निर्भर रहते हैं। अगर संस्थापक सक्रिय रूप से मुंबई, बेंगलुरु और नई दिल्ली के निवेशक नेटवर्क में नहीं जुड़े हैं, तो यह बात और सच साबित होती है। 9 यूनिकॉर्न्स का लक्ष्य इन स्टार्ट-अप के लिए वैसा ही 'दोस्त और परिवार' जैसा निवेशक बनना है। हालांकि यहां अंतर यह है, कि स्टार्ट-अप को भारत के टिअर 1, 2, 3 और 4 शहरों में मौजूद भारतीय व्यापार समुदायों के इसके विशाल नेटवर्क से जुड़ने की सहूलियत मिलती है, जिससे स्टार्ट-अप पूरे भारत में अपना प्रसार करने में सक्षम होते हैं।

ओएनजीसी का शुद्ध लाभ अप्रैल-जून में 92 प्रतिशत गिरा

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष पहली तिमाही में 92 प्रतिशत गिर गया। इसकी बड़ी वजह तेल कीमतों का लगभग आधा हो जाना और गैस कीमतों के दशक के सबसे निचले स्तर पर चले जाना रहा। कंपनी ने एक बयान में मंगलवार को यह जानकारी दी। कंपनी का एकल शुद्ध लाभ अप्रैल-जून तिमाही में 496 करोड़ रुपये रहा जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के 5,980 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ से 91.7 प्रतिशत कम है। कंपनी ने कहा कि इतना लाभ भी कंपनी को उसके कच्चे तेल उत्पादन पर उपकर का भुगतान देरी से करने पर हुआ है। यहां तक कि सरकार से राहत की उम्मीद में कंपनी ने रॉयल्टी का भी भुगतान नहीं किया। कंपनी ने कहा कि रॉयल्टी का भुगतान उसने जून के अंत में किया जबकि उपकर का भुगतान जुलाई में ही किया जा सका। देशभर में 24 मार्च से लगे लॉकडाउन ने ईंधन की मांग को प्रभावित किया। कंपनी की आय समीक्षावधि में 51 प्रतिशत गिरकर 13,011 करोड़ रुपये रही।

कीमतों में गिरावट से नुकसान

ओएनजीसी ने कहा कि आलोच्य तिमाही में कंपनी को प्रति बैरल कच्चे तेल के लिए औसत 28.72 डॉलर प्राप्त हुए। जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह दाम 66.32 डॉलर प्रति बैरल था। इसी तरह गैस की कीमतें भी 35.2 प्रतिशत गिरकर 2.39 डॉलर प्रति दस लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आ गयी। समीक्षावधि में कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ 1,090 करोड़ रुपये रहा। यह पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के 7,120 करोड़ रुपये के एकीकृत लाभ से 84.7 प्रतिशत कम है। कंपनी का कच्चा तेल उत्पादन इस दौरान पिछले वर्ष की भांति ही 48 लाख टन रहा। जबकि गैस उत्पादन 12.3 प्रतिशत घटकर 5.4 अरब घन मीटर रह गया। चालू वित्त वर्ष में अब तक कंपनी ने तीन गैस-तेल क्षेत्रों की खोज की है। इसमें केजी ब्लॉक और त्रिपुरा में प्राकृतिक गैस की खोज शामिल है।

चीन की जगह लोकल सप्लायर्स से कच्चा माल खरीद रहीं FMCG कंपनियां

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

गलवान घाटी की घटना के बाद मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था। इसके तहत वोकल फॉर लोकल की अपील की गई। हर सेक्टर में चीन समेत अन्य देशों पर निर्भरता कम करने की अपील अब रंग ला रही है। भारत की बड़ी-बड़ी एफएमसीजी कंपनियां जैसे कि हिन्दुस्तान यूनीलीवर, डाबर और गोदरेज कन्ज्यूमर ने कच्चे माल के मामले में चीन पर निर्भरता घटानी शुरू कर दी है।

लोकल कंपनियों से खरीद

इन कंपनियों ने अब लोकल कंपनियों से कच्चे माल खरीदना शुरू कर दिया है। गोदरेज कन्ज्यूमर के सीईओ- इंडिया ऐंड SAARC, सुनील कटारिया ने कहा कि हम अब लोकल इंपोर्ट पर फोकस कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अभी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर चीन है। ऐसे में उसे रिप्लेस करने में थोड़ा समय जरूर लगेगा।

#BoycottChina मुहिम रंग लाई

दशकों से चीन ग्लिसरीन, कलरिंग एजेंट्स, हर्बल एक्सट्रैक्ट, पैकेजिंग प्रॉडक्ट का लीडर रहा है। स्किन केयर, बाथ ऐंड बॉडी प्रॉडक्ट का भी बड़े पैमाने पर निर्यात करता है। दो महीने पहले गलवान घाटी घटना के बाद ऐंटी चाइना सेंटिमेंट में तेजी आने लगी। चीन पर निर्भरता कम करने को लेकर #BoycottChina मुहिम रंग लाई है।

यूनीलीवर चीन पर निर्भरता घटाएगी

जुलाई में हिन्दुस्तान यूनीलीवर ने कहा कि वह चीन पर अपनी निर्भरता कम करेगी। कंपनी के चेयरमैन संजीव मेहता ने 87वें ऐनुअल जनरल मीटिंग में कहा कि कंपनी चीन से सालाना 429 करोड़ का कच्चा सामान और पैकिंग मटीरियम आयात करती है। अब हमारा फोकस धीरे-धीरे इसे घटाने पर है।

राष्ट्रपति चुनाव से पहले अमेरिका-भारत में हो सकता है 'छोटा व्यापार करार'

वाशिंगटन। एजेंसी

अमेरिका और भारत के बीच राष्ट्रपति चुनाव से पहले एक छोटा व्यापार समझौता हो सकता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव तीन नवंबर को है। अमेरिका-भारत रणनीतिक एवं भागीदारी मंच (यूएसआईएसपीएफ) द्वारा सोमवार को वर्चुअल तरीके आयोजित तीसरे भारत-अमेरिका नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमेरिका के उप विदेश मंत्री स्टीफन बेगुन ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में आपस में काफी अच्छा रिश्ता है। दोनों एक व्यापार करार को लेकर प्रतिबद्ध हैं। ऐसे में एक छोटे करार की संभावना बनती है।" बेगुन से अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से पहले एक छोटे व्यापार करार को लेकर संभावना के बारे में पूछा गया था। भारत में अमेरिका के पूर्व राजदूत रिचर्ड वर्मा ने उनसे सवाल किया, "क्या आपको लगता है कि चुनाव से पहले छोटे व्यापार करार की संभावना है?" बेगुन ने इसपर कहा कि इसकी संभावना बनती है। हालांकि, इसके लिए हमें अधिक ऊर्जा लगानी होगी। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, बीते वित्त वर्ष 2019-20 में अमेरिका लगातार दूसरे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा। बीते वर्ष में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 88.75 अरब डॉलर रहा, जो 2018-19 में 87.96 अरब डॉलर था। अमेरिका उन कुछ देशों में से है जिनके साथ भारत व्यापार अधिशेष की स्थिति में है। 2019-20 में यह व्यापार अंतर 17.42 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 16.86 अरब डॉलर था।

विनिर्माण गतिविधियों ने पकड़ी रफ्तार, तेजी का दे रहे हैं संकेत

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भारत की विनिर्माण गतिविधियों में अगस्त में वृद्धि दर्ज हुई है। कारोबारी परिचालन शुरू होने के बाद उत्पादन में सुधार, नए ऑर्डर तथा उपभोक्ता मांग बेहतर होने से विनिर्माण गतिविधियां भी बढ़ी हैं। आईएचएस मार्किट इंडिया का विनिर्माण खरीद प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) अगस्त में बढ़कर 52 हो गया है। यह जुलाई में 46 पर था। इससे विनिर्माण क्षेत्र के परिचालन में सुधार का संकेत मिलता है। इससे पहले लगातार चार महीनों तक विनिर्माण गतिविधियों में गिरावट आई थी।

लगातार 32 माह तक वृद्धि दर्ज करने के बाद अप्रैल में यह इंडेक्स नीचे चला गया था। पीएमआई के 50 से ऊपर होने का मतलब गतिविधियों में सुधार से है। यदि यह 50 से नीचे रहता है, तो इसका आशय है कि गतिविधियां घटी हैं। आईएचएस मार्किट की अर्थशास्त्री श्रेया पटेल ने कहा, अगस्त के आंकड़े भारत के विनिर्माण क्षेत्र की सेहत में सुधार को दर्शाते हैं। घरेलू बाजारों की मांग बढ़ने से उत्पादन में सुधार हुआ है। हालांकि, नए ऑर्डर बढ़ने के बावजूद विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियों में कटौती का सिलसिला जारी है। पटेल ने कहा, हालांकि, अगस्त में सभी कुछ सकारात्मक नहीं था। कोविड-19 की वजह से पैदा हुई अड़चनों के चलते आपूर्ति का समय बढ़ गया है। इस बीच, क्षमता पर दबाव के बावजूद नौकरियों में गिरावट जारी है। कंपनियों को अपने कामकाज के लिए उपयुक्त श्रमिक नहीं मिल पा रहे हैं।

सर्वे में कहा गया है कि नए ऑर्डरों पर विदेशी निर्यात में कमी का असर पड़ा है। कंपनियों का कहना है कि विदेशी बाजारों की मांग कमजोर है। हालांकि, भारतीय विनिर्माताओं को मिले नए ऑर्डरों में फरवरी से सुधार आ रहा है। पटेल ने कहा कि मूल्य के मोर्चे पर आपूर्ति में कमी तथा परिवहन संबंधी विलंब के चलते कच्चे माल की लागत बढ़ी है। इससे अगस्त में उत्पादन की लागत बढ़ी है। सर्वे में कहा गया है कि भारतीय विनिर्माता अगले 12 महीनों को लेकर आशान्वित हैं। विनिर्माताओं को उम्मीद है कि इस दौरान कोविड-19 का दौर समाप्त हो जाएगा और ग्राहकों की मांग सुधरेगी।

हम होंगे कामयाब...

श्री ब्रजेश गांधी
लेखक वरिष्ठ उद्योगपति और समाजसेवी है

आज से करीब 2 महीने पहले एक कॉलेज के प्राचार्य का फोन आया जो मेरे मित्र भी हे, वो इस करोना काल से निर्मित समस्याओं से परेशान थे, उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पढ़ाई में प्राध्यापक ओर स्टूडेंट्स दोनों को ही मजा नहीं आ रहा, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अपने भविष्य को लेके खासे चिंतित है, कैंपस इंटरव्यू का क्या होगा, कम्पनी केंपस केसे आएगी, इंटरव्यू केसे होंगे, नौकरी मिलेगी कि नहीं, यह सब सवालों के चलते पढ़ने में ध्यान नहीं लगा पा रहे, उन्होंने मुझे बात बात में कहा 'वो आपकी पिछली क्लास के बाद काफी प्रसन्न थे, क्या पता आपकी एक ओर क्लास उनके मानस में बदलाव ले आए, तो क्या इन स्टूडेंट्स कि आप एक क्लास लेंगे?' मेने कहा ' जरूर कोशिश करने में क्या हर्ज है, में उनके माइंडसेट को बदलने की कोशिश जरूर करूंगा, आगे प्रभु कि मर्जी।' तो पाच दिन बाद का ऑनलाइन क्लास का समय निर्धारित हो गया, मुझे लगा एक साथ क्लास के सभी बच्चो को समझ ना ओर उनसे ऑनलाइन बात करना आसान नहीं होगा, तो मेने कोलेज की आईटी टीम से बोला की, क्लास के 50 बच्चो को उनकी पसंद के अनुसार पाच ग्रुप में बांट कर सभी पाच ग्रूपो की कल एक एक क्लास रखे , अब पहली क्लास का समय हुआ, ओर पहला बेच ऑनलाइन आया, मेने देखा में जन उनसे थोड़े वक्त पहले रूबरू मिला था तब, जो चमक ओर उत्साह उनके चहेरे पर था वो आज कहीं नजर नहीं आ रहा था, खेर बातचीत चालू हुई, शुरुआत थोड़ी ढीली ही थी लेकिन बच्चे कम होने से कुछ ही देर में क्लास पर मेने पकड़ बना ली। धीरे धीरे बच्चे भी खुलने लगे, सब के मन में वहीं शंका ने घर कर लिया था, ये महामारी के चलते आगे उनका भविष्य क्या होगा, अब जब वो अपने स्नातक कॉर्स के आखरी साल में है, ओर जून 2021 तक उनका कोर्स पूरा हो जाएगा, इस बीच हर साल जैसे कंपनियां केंपस आएगी (या नहीं आएगी) ? आएगी तो कितने बच्चो को नौकरी देगी ? क्या पैकेज ऑफर करेगी ? जिस बच्चो को नौकरी ना मिली तो क्या होगा ? यह सब सवालों की एक झड़ी सी लग गई, थोड़े समय तक में चुपचाप यह सब सुनता रहा, ओर मन ही मन यह सोचा कि अच्छा हुआ जो मेने बेच साइज़ छोटी कर दी, अन्यथा बड़ी मुश्किल होती 50 बच्चो को एक साथ सुनने में। अब जब सवालों कि बोछार कम हुई तो मेने सब का माइक म्यूट किया ओर मेने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, ' फ्रेंड्स यह समय, आज जिससे हम ओर पूरा विश्व एक साथ गुजर रहे है, ये समय न भूतो न भविष्यति है, इससे आगे क्या होगा ? उसका शायद किसी के पास कोई जवाब नहीं है, ओर इसका जवाब हमे कोई बाहर से दे भी नहीं पाएगा शायद, हमें यह जवाब हमारे भीतर ही ढूंढने होंगे।' वो लोगो की आंख में कुछ ओर सवाल उभर आए थे, तो मेने उनके माइक फिर से ऑन किये, अब एक साथ बोलने कि जगह वो लोग एक एक कर बोलने लगे, 'सर अगर हमे नौकरी नहीं मिली तो ? हमने बैंक से इस कोर्स के लिए बड़ी लोन ली है, अगर हमे नौकरी नहीं मिलेगी ओर जब कॉर्स के बाद तुरंत उसकी किस्त चालू हो जाएगी तब क्या होगा ? हम मे से कुछ लोगो के पेरेंट शायद ये एक्स्ट्रा बोझ ना उठा सके' उनकी बातो मे दम था, फिर एक बार मेने बोलना शुरू किया ओर उनके माइक म्यूट किए । 'देखो दोस्तो जैसे कि मेने पहले बताया ये परिस्थिति हे तो बड़ी ही विकट लेकिन ऐसा भी नहीं की इससे कोई रास्ता ना निकले, ओर आप सब एक साथ मिलकर इससे रास्ता निकाल ने कि कोशिश करेंगे, आत्मनिर्भर बनने से ज्यादा जरूरी , हमे परस्पर निर्भर बनना है, ओर सकारात्मकता के साथ प्रयास करेंगे तो आपकी ये नौकरी ओर आने वाले भविष्य को लेके निश्चिंत हो जाओगे।' उन सब के चहरो पे आश्चर्य भाव में साफ पढ़ पा रहा था, उनके चहेरे की तंग लकीरें थोड़ी ढीली पड़ी थी, ओर अब वो मुझे सुनने समझ ने कि स्थिति में दिख रहे थे, अब मेने फिर बोलना शुर किया, 'देखो दोस्तो आज जब सब बड़ी छोटी कंपनी के हालात इस महामारी कि वज़ह से पहले जैसी नहीं है, तो क्या तुम्हे तुम्हारी पढ़ाई ओर काबिलियत पर कोई शक है ? क्या कोई नौकरी देगा तो ही आपकी आगे की जिंदगी चलेगी, आप सब साथ मिल कर कुछ रचनात्मक तरीके नहीं सोच सकते अपने करियर के लिए में ओर आपका कोलेज मैनेजमेंट आपका इस काम में याथौचित मार्गदर्शन ओर सहाय करने की कोशिश करेंगे।'

अब उनकी आंखो में विश्वास दिख रहा था तो मेने उनसे आपस में विचार करके पाच दिन बाद अपने विचार संयुक्त क्लास में रखने को बोल कर मेने यह ग्रुप कि मीटिंग खत्म करी।

आगे ओर चार ग्रुप के साथ यही विचार विमर्श हुआ, ओर आखरी में वो दिन आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था, मन में ये बोझ था कि सभी ग्रुप क्या क्या तरीके सोच कर आएं।

लॉकडाउन नियमों में राहत का खुदरा विक्रेताओं के संघ ने किया स्वागत

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आरएआई) ने केंद्र सरकार के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को 'निषिद्ध क्षेत्र' के अलावा अन्य किसी जगह बिना अनुमति लॉकडाउन नहीं लगाने के निर्देश का स्वागत किया। इससे देश के खुदरा क्षेत्र उद्योग ने बड़ी राहत की सांस ली है। आरएआई, विभिन्न खुदरा श्रृंखला चलाने वाली कंपनियों का संघ है। संघ

ने एक बयान में कहा कि गृह मंत्रालय के खुदरा क्षेत्र को सभी दिन खुला रखने के निर्देश के बावजूद स्थानीय स्तर पर सरकारें सप्ताहांतों में आंशिक लॉकडाउन लगा रही थीं। आरएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार राजगोपालन ने कहा, '' आजीविका बहुत बहुत अहम है, और हमारा मानना है कि किसी भी तरह की पाबंदी बहुत सावधानीपूर्वक और जीवन एवं आजीविका के बीच संतुलन को समझकर लगायी जानी चाहिए। उन्होंने अर्थव्यवथा को फिर खोलने के लिए गृह मंत्रालय और आंतरिक व्यापार एवं उद्योग संवर्द्धन विभाग के प्रयासों की भी सराहना की। आरएआई ने कहा कि खुदरा कंपनियां मुख्य तौर पर आने वाले त्यौहारी सीजन से अपने कारोबार में सुधार की उम्मीद लगा कर बैठी हैं। खुदरा उद्योग में सुधार का लाभ पूरी आपूर्ति श्रृंखला मसलन विनिर्माण,मनोरंजन और दस्तकारी को होगा। यह अर्थव्यवस्था को गति देगा।

जीएसटीआर में व्यापारियों के लिए नई सुविधा

हर माह 12 तारीख को ऑनलाइन दिखेगा जीएसटी क्रेडिट

जलंधर। एजेंसी

जीएसटी कौंसिल ने जीएसटीआर फार्म में व्यापारियों को नई सुविधा दे दी है। अब फार्म नंबर जीएसटीआर-2बी का डेटा ज्यादा पारदर्शिता के साथ व्यापारी अपने कंप्यूटर पर देख सकेंगे। जो ताजा रिटर्न भरी जाएगी, उसमें इस सुविधा का लाभ मिलेगा। जीएसटी कौंसिल के नए आदेश के अनुसार हर महीने 12 तारीख तक पिछले महीने का जीएसटी रिफंड यानी क्रेडिट होगा, वो व्यापारी ऑनलाइन उक्त फार्म में देख सकेंगे। जो माल विदेश से आयात किया होगा, उस पर जो आईजीएसटी सरकार को जमा कराया है, वह भी ऑनलाइन दिखेगा। पहले पुरानी व्यवस्था के अनुसार फार्म-2ए में आयात किए माल पर दिए टैक्स की रकम ऑनलाइन नहीं मिलती थी। हर व्यापारी इसका हिसाब अपने पास अलग से रखता था। जीएसटी मामलों के एक्सपर्ट एडवोकेट अमित बजाज ने कहा कि इसमें सरकार का ये कहना है कि जो 2बी नामक फार्म में आपका जीएसटी रिफंड नजर आएगा, वह ऑनलाइन दिखाई देने से जीएसटीआर 3 भी रिटर्न भरने में उससे मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने जीएसटी रिफंड के बारे में ज्यादा जानकारी देने को ऑनलाइन सुविधा प्रदान कर दी है लेकिन पंजाब सरकार के पुराने वैट कानून के तहत मांगे जा रहे सी फार्म को लेकर व्यापारी लगातार परेशान हो रहे हैं। व्यापार सेना पंजाब के प्रेसिडेंट रविंदर धीर ने कहा कि एक सितंबर तक टैक्सेशन विभाग ने कहा था कि टैक्स की पेनल्टी की रकम पर ब्याज लेंगे, अगर सी फार्म व्यापारियों ने जमा न कराए। रविंदर धीर ने कहा कि कोरोना काल में व्यापार मंदी में है, विभिन्न राज्यों में बाढ़ आई है, लॉकडाउन की शर्तें चल रही हैं, व्यापार तबाह हो रहा है तो ये फार्म कैसे व्यापारी भरेगा। पिछले 4 साल के फार्म भरने को कहा गया है। उधर, विधायक राजिंदर बेरी ने बताया कि हमने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को मसला बताया है। बकौल बेरी हमने मुख्यमंत्री से कहा है कि पहले तो फार्म भरने का नोटिस स्थगित करें और इस दौरान नई डीम्ड असेस्मेंट लाएं।

सामान्य स्तर के करीब पहुंची बिजली खपत, अब रह गया केवल इतना अंतर

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

आर्थिक गतिविधियां बढ़ने के साथ बिजली खपत अगस्त में कोविड-19 के पहले के स्तर पर लगभग पहुंच गई है। पिछले महीने कुल बिजली खपत 110.57 अरब यूनिट रही जो पिछले साल के इसी माह के मुकाबले महज 0.85 प्रतिशत कम है। उम्मीद है कि इस महीने यह सामान्य स्तर से ऊपर पहुंच जाएगी। बिजली मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार पिछले साल अगस्त महीने में बिजली खपत 111.52 अरब यूनिट थी। आंकड़ों के अनुसार सरकार के आर्थिक गतिविधियों में छूट और उमस भरी गर्मी के साथ बिजली खपत विशेष रूप से अगस्त महीने में बढ़ी। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए 25 मार्च से 'लॉकडाउन' लगाया था। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित हुई। इस कारण बिजली मांग के साथ खपत कम हुई। जुलाई महीने में बिजली खपत में कमी का अंतर कम होकर 3.6 प्रतिशत पर आ गया था। इस दौरान बिजली खपत 112.24 अरब यूनिट रही जबकि एक साल पहले 2019 के इसी माह में खपत 116.48 अरब यूनिट थी।

कब तक होगी सामान्य

जून में बिजली खपत 10.93 प्रतिशत घटकर 105.08 अरब यूनिट थी जबकि एक साल पहले 2019 के इसी महीने में खपत 117.98 अरब यूनिट थी। मई और अप्रैल में बिजली खपत में क्रमशः 14.86 प्रतिशत और 23.21 प्रतिशत की कमी आई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार 'लॉकडाउन' में ढील देकर आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने पर जोर दे रही है। इसका लाभ हो रहा है और बिजली खपत पिछले साल के सितंबर महीने के मुकाबले इस माह सामान्य स्तर से ऊपर जा सकती है। इस बीच, बिजली की अधिकतम मांग को पूरा करने के लिए आपूर्ति अगस्त महीने में 1,67,490 मेगावाट रही जो पिछले साल इसी महीने में 1,77,520 मेगावाट के मुकाबले 5.65 प्रतिशत कम है।

आत्मनिर्भर भारत योजना

प्रवासी मज़दूरों के लिए आवंटित खाद्यान्न में से सिर्फ 33 फीसदी का वितरण हुआ

नई दिल्ली। एजेंसी

कोरोना वायरस के चलते देशव्यापी लॉकडाउन के कारण अपने घरों को लौटने को मजबूर हुए और खाद्यान्न संकट से जूझ रहे प्रवासी मजदूरों के लिए आवंटित खाद्यान्न में से सिर्फ 33 फीसदी राशन का वितरण हो पाया है। बीते एक सितंबर को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत करीब आठ लाख टन खाद्यान्न वितरण की योजना बनाई थी, लेकिन 31 अगस्त 2020 तक इसमें से सिर्फ 2.65 लाख टन खाद्यान्न का वितरण हो पाया है। मंत्रालय के अनुसार योजना के तहत मई महीने में 2.35 करोड़, जून महीने में 2.48 करोड़, जुलाई में 31.43 लाख और अगस्त में 16 लाख लोगों यानी कुल करीब 2.65 करोड़ लोगों को दस-दस किलो खाद्यान्न वितरित किया गया है।खास बात ये है कि इस तरह के लचर प्रदर्शन के बावजूद भारत सरकार ने इस योजना को 'सफल' घोषित कर दिया है।

व्यापक आलोचना और महामारी के दौरान सभी लोगों को राशन मुहैया कराने के लिए उठी मांगों के बाद केंद्र सरकार ने 15 मई 2020 को घोषणा किया था कि मई और जून महीने के लिए कुल आठ करोड़ ऐसे प्रवासी मजदूरों, फंसे हुए लोगों और जरूरतमंदों को भी मुफ्त राशन दिया जाएगा, जिनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)

या राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन कार्ड नहीं है और वे खाद्य योजनाओं के दायरे में नहीं है।

हालांकि सरकार ने अभी तक ये भी स्पष्ट नहीं किया है कि उन्होंने किस आधार पर ये आकलन किया था कि सिर्फ आठ करोड़ लोग ही ऐसे लोग हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। बहरहाल, सरकार ने कहा था कि ऐसे सभी व्यक्ति को दस किलो खाद्यान्न (मई और जून महीने के लिए) और प्रति परिवार दो किलो चना मुफ्त में दिया जाएगा। लेकिन अब सरकार इससे भी एक कदम आगे निकल गई है और कम वितरण पीछे उनकी दलील ये है कि राज्य सरकारें और केंद्रशासित प्रदेश ऐसे सिर्फ करीब 2.8 करोड़ लोगों की ही पहचान कर पाए हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और वे आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत राशन पाने के लिए पात्र हैं।

जबकि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के आंकड़े दर्शाते हैं कि जून, 2020 के अंत तक राज्य में इस योजना के तहत वितरण के लिए 6.38 लाख टन खाद्यान उठाया था। मंत्रालय ने दावा किया, 'इस योजना में पूरा लचीलापन था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी योजना का लाभार्थी इससे वंचित न रह जाए। इसके लिए योजना के तहत पात्र प्रवासियों/फंसे हुए प्रवासियों और अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें खाद्यान्न वितरण की जिम्मेदारी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को दी गई थी। उन्होंने आगे कहा, 'इसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को केंद्र या राज्य योजना के तहत राशन कार्ड नहीं पा सके या संकट की स्थिति में खाद्यान्न पाने से वंचित रह गए लोगों की पहचान करने के लिए जिला/क्षेत्र स्तर के अधिकारियों को अपने हिसाब से दिशा-निर्देश और एसओपी जारी करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई थी।

आधे घंटे में सामान पहुंचाएगी सामान ऐमजॉन, कंपनी को मिली हरी झंडी

न्यूयॉर्क। एजेंसी

वह दिन दूर नहीं है जब आप ऐमजॉन (Amazon) से कोई सामान मंगाएं और वह आधे घंटे या उससे भी कम समय में आपके दरवाजे पर पहुंच जाए। दुनिया के सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस की कंपनी ड्रोन से डिलीवरी के लक्ष्य को साथ लेकर चल रही है और सोमवार को वह इसे पूरा करने की दिशा में एक कदम और आगे निकल गई। अमेरिका के संघीय विमानन प्रशासन (एफएए) का कहना है कि उसने ऐमजॉन को पैकेज की डिलिवरी ड्रोन से करने की अनुमति दे दी है। ऐमजॉन ने कहा कि यह अनुमति एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन इसके साथ ही उसने जोड़ा कि वह अभी ड्रोन की उड़ान और अन्य परीक्षण कर रही है। कंपनी ने यह नहीं बताया कि वह ग्राहकों को कब तक ड्रोन के जरिए डिलिवरी शुरू करेगी। ई-कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी कई साल से ड्रोन के जरिए सामानों की आपूर्ति पर काम रही है। लेकिन इसे कई तरह की नियामकीय अड़चनों का सामना करना पड़ा है। ऐमजॉन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जेफ बेजोस ने 2013 में एक टीवी साक्षात्कार में कहा था कि कंपनी पांच साल में ग्राहकों को ड्रोन के जरिए डिलिवरी शुरू कर देगी।

कितना सामान ढो सकता है ड्रोन

ऐमजॉन को पार्ट 135 एयर कैरियर सर्टिफिकेट दिया गया है। इससे कंपनी अपने प्राइम एयर ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकेगी। ऐमजॉन का कहना है कि उसे अपने ऑपरेशंस की सेफ्टी का प्रमाण देना होगा और एफएए के समक्ष इसका प्रदर्शन करना होगा। प्राइम एयर के वाइस प्रेजिडेंट डेविड कार्बन ने कहा कि यह सर्टिफिकेट मिलना इस बात का प्रमाण है कि एफएए को कंपनी के ऑपरेटिंग और सेफ्टी प्रॉसीजर पर पूरा भरोसा है। कंपनी ने पिछले साल लास वेगास में एक इलेक्ट्रिक हेक्सागॉन ड्रोन के बारे में बताया था जो 5 पाउंड तक सामान ले जा सकता है। कंपनी का कहना है कि इसमें ऐसी तकनीक लगी है कि यह रास्ते में आने वाली दूसरी चीजों से नहीं टकराता है। ऐमजॉन दुनिया के कई देशों में एक दिन में डिलीवरी दे रही है। लेकिन उसका लक्ष्य डिलीवरी टाइम को और कम करना है।

तीन कंपनियों को सर्टिफिकेट

ऐमजॉन पार्ट 135 एयर कैरियर सर्टिफिकेट पाने वाली तीसरी कंपनी है। इससे पहले गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट की विंग एविएशन और यूपीएस फ्लाइट फॉरवर्ड को यह सर्टिफिकेट मिल चुका है। लेकिन किसी भी कंपनी ने अब तक बड़े पैमाने पर ड्रोन से डिलीवरी की शुरुआत नहीं की है।

फार्मा, एपीआई और कैमिकल्स उद्योग में प्रवेश को तैयार विकास इको टेक लिमिटेड, 75 करोड़ के निवेश की तैयारी

मुम्बई। आईपीटी नेटवर्क

बीएसई तथा एनएसई में सूचीबद्ध, विकास इकोटेक लिमिटेड विभिन्न उद्योगों में प्रवेश की ओर भी बढ़ रही है। विकास इकोटेक एक इंटीग्रेटेड-स्पेशियलिटी उत्पाद समाधान प्रदान करने वाली कम्पनी है, जो कि उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले इको फ्रेंडली रबर प्लास्टिक कंपाउंड्स और एडिटिव्ज़ का उत्पादन करती है। कम्पनी द्वारा यह सूचना प्रदान की गई है कि इसके बोर्ड ने कम्पनी के लिए फार्मास्युटिकल्स, एपीआई और कैमिकल उद्योग में मौजूद संभावनाओं के मद्देनजर कम्पनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (कम्पनी के निदेशकों के समूह) द्वारा नियुक्त एक्सपर्ट कमेटी द्वारा तैयार रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। उल्लेखनीय है कि इस विशेषज्ञ कमेटी को व्यवसायिक विस्तार के हिसाब से व्यवसायिक संभावनाओं की पहचान के मूल्यांकन के लिए नियुक्त किया गया था। इसके साथ ही कम्पनी ने आने वाले 2 सालों में नए उद्योगों में या ऑर्गेनिक अथवा इनऑर्गेनिक दोनों तरीकों से वृद्धि के लिए एक रणनीतिक साझेदारी के जरिये 75 करोड़ रुपये के निवेश का निर्णय किया है। विकास इकोटेक ने हाल ही में यह घोषणा भी की थी कि कोविड-19 के वर्तमान संकट के बावजूद, कम्पनी ने अपने फ्लैगशिप उत्पाद, इकोफ्रेंडली 'ऑर्गेनिक पीवीसी स्टेबलाइज़र्स' को यूनाइटेड स्टेटस ऑफ अमेरिका (दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनोशन मार्केट) को बिना किसी बाधा के निरन्तर एक्सपोर्ट किया।

जेनरिक इंजीयरिंग ने पाया 101.95 करोड़ रुपये का ऑर्डर

मुम्बई। आईपीटी नेटवक

बीएसई में सूचीबद्ध, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र का बड़ा नाम 'जेनरिक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने हाल ही में एक बड़ी सफलता अपने नाम को है। कम्पनी को विभिन्न इंस्टिट्यूशनल प्रोजेक्ट्स के लिए विभिन्न क्लाइंट्स से 101.95 करोड़ रुपये का नया ऑर्डर प्राप्त हुआ है। इसमें 30 करोड़ रुपये का कंस्ट्रक्शन ऑर्डर आदित्य बिरला ग्रुप से एक स्कूल के निर्माण हेतु भी शामिल है। इन नए ऑर्डर्स के साथ ही कम्पनी की वर्तमान आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक 1,067.54 करोड़ पर पहुंच गई है। उक्त ऑर्डर्स की प्राप्ति के बारे बताते हुए श्री मनीष पटेल, कम्पनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, ने कहा-'अपने इस नए ऑर्डर को लेकर हम सभी बेहद उत्साहित हैं। खासतौर पर इसलिए क्योंकि यह ऐसे समय मे हमारे पास आया है जब पूरा कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर एक चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है। हम लॉकडाउन के हर चरण के खुलने के साथ, धीरे धीरे अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं, हालांकि अभी भी श्रमिकों की कमी एक बाधा बनी हुई है। हमें उम्मीद है कि इस वित्तीय वर्ष की द्वितीय छमाही में काम सामान्य स्तर पर शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारियों/श्रमिकों की कमी के मुद्दे को सुलझाने के लिए, कम्पनी ने भारत के उत्तरी राज्यों में प्रोजेक्ट्स के लिए बिडिंग की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। ये वही स्थान हैं जहां अधिकांश मजदूर लॉकडाउन के दौर में चले गए हैं। हम इसके साथ ही तेजी से नये प्रोजेक्ट्स के लिए भी बिडिंग (नीलामी) की प्रक्रिया कर रहे हैं, खासकर पब्लिक सेक्टर में, ताकि एक मज़बूत ऑर्डर बुक तैयार की जा सके। इससे हम लॉकडाउन के दौरान हुई राजस्व की क्षति की पूर्ति आने वाली तिमाही में कर सकेंगे।'

औद्योगिक कर्मचारियों के लिये खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में मामूली घटकर 5.33 प्रतिशत रही

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

कुछ खाद्य पदार्थों की कीमतें कम होने से औद्योगिक कर्मचारियों के लिये खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई महीने में मामूली घटकर 5.33 पतिशत रही। एक साल पहले इसी महीने में यह 5.98 प्रतिशत थी। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ''सालाना आधार पर सभी जिंसों की मुद्रास्फीति इस साल जुलाई में 5.33 प्रतिशत रही। एक महीने पहले जून 2020 में यह 5.06 प्रतिात और एक साल पहले जुलई 2019 में यह 5.98 प्रतिशत थी।'' खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर जुलाई महीने में 6.38 प्रतिशत रही। यह पिछले महीने जून में 5.49 प्रतिशत और एक साल पहले जुलाई 2019 में 4.78 प्रतिशत थी। अखिल भारतीय औद्योगिक कर्मचारियों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) जुलाई 2020 में 4 अंक बढ़कर 336 अंक रहा। प्रतिशत के हिसाब से पिछले माह के मुकाबले यानी जून-जुलाई के बीच इसमें 1.20 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि एक साल पहले इसी माह की तुलना में 0.95 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। श्रम मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार मौजूदा सूचकांक में सर्वाधिक तेजी आवास समूह से आयी है। इसका कुल बदलाव में योगदान (₹) 2.28 प्रतिशत रहा। जिंसों के आधार पर गेहूं आटा, सरसों तेल, दूध (भैंस), हरी मिर्च, बैगन, पालक, परवल, आलू, टमाटर रसोई गैस, लकड़ी, बस का किराया, पेट्रोल, सिलाई शुल्क आदि के कारण सूचकांक में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, दूसरी तरफ चावल, ताजी मछली, बकरे का मांस, पाल्ट्री (चिकेन), नींबू आदि सस्ता होने से सूचकांक में तेजी पर अंकुश लगा। केंद्र के स्तर पर जमशेदपुर में सर्वाधिक 36 अंक की वृद्धि हुई। उसके बाद हल्दिया (23 अंक), तिरूचिरापल्ली (13 अंक), कोडरमा और फरीदाबाद (12-12 अंक), श्रीनगर (11 अंक), लखनऊ और दमदम, तिनसुकिया (10-10 अंक) का स्थान रहा। आंकड़ों के अनुसार दो केंद्रों में 8-8 अंक, पांच केंद्रों में 7-7 अंक, आठ केंद्रों में 6-6 अंक, सात केंद्रों में 5-5 अंक, दस केंद्रों में 4-4 अंक, नौ केंद्रों में 3-3 अंक, नौ दूसरे केंद्रों पर 2-2 अंक और नौ अन्य केंद्रों में 1-1 अंक की वृद्धि हुई। इसके विपरीत मदुरै में 5 अंक की गिरावट आयी। इसके अलावा एक केंद्र में 3 अंक, एक और केंद्र में 2 अंक और दो केंद्रों में 1-1 अंक की गिरावट आयी। शेष छह केंद्रों में सूचकांक स्थिर रहे। कुल 31 केंद्रों का सूचकांक आखिल भारतीय सूचकांक से अधिक है जबकि 45 केंद्रों में यह आखिल भारतीय स्तर से नीचे है। छिंदवाड़ा और जालंधर केंद्रों का सूचकांक आखिल भारतीय स्तर के बराबर है। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा, ''मुख्य रूप से आवास किराया और आलू, टमाटर, औषधि, बस किराया, पेट्रोल आदि के दाम बढ़ने से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बढ़ा है।'' सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिये महंगाई भत्ते के निर्धारण में सीपीआई-आईडब्ल्यू मानक है। मंत्री ने कहा कि सीपीआई-आईडब्ल्यू (रहन-सहन की लागत) में वृद्धि का संगठित क्षेत्र में काम करने वाले औद्योगिक कर्मचारियों के अलावा सरकारी कर्मचारियों के वेतन/मजदूरी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्रम ब्यूरो के महानिदेशक डी एस नेगी ने कहा, ''कोविड-19 के कारण आंकड़ा संग्रह में कर्मचारियों को हुई परेशानी के बावजूद श्रम ब्यूरो बिना किसी बाधा के निर्धारित समय पर मासिक सूचकांक लाने में सफल रहा है।'' उन्होंने कहा कि सूचकांक में वृद्धि का मुख्य कारण आवास और खाद्य समूह के उत्पाद हैं। आवास सूचकांक हर साल छह महीने के आधार जनवरी और जुलाई में संशोधित होता है। खाद्य वस्तुओं की श्रेणी में आलू और टमाटर बढ़ोतरी के लिये प्रमुख कारक रहें। इसके अलावा रसोई गैस और पेट्रोल के कारण कीमतें बढ़ीं।

मजबूत होते रुपए से आपको मिलेंगे ये फायदे

किसानों से लेकर भारतीय कंपनियों को मिलेगा लाभ

मुंबई। एजेंसी

डॉलर के मुकाबले रुपया बीते कुछ दिनों में लगातार मजबूत हुआ है। दरअसल विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में पूंजी डाली है जिसके चलते रुपए में मजबूती का रुख है। बीते हफ्ते से लेकर अबतक रुपए की चाल ज्यादातर मजबूत रही है। इस हफ्ते की बात करें तो मंगलवार 39 पैसे की मजबूती के साथ खुला था। वहीं बीते हफ्ते रुपए की चाल ज्यादातर मजबूत रही थी। देश की करेंसी मजबूत होने का फायदा एक ओर जहां इंपोर्ट करने वाली कंपनियों को मिलता है वहीं इससे आम आदमी से लेकर किसानों तक को इसका लाभ मिलता है।

कैसे तय होती है रुपए की चाल

करेंसी एक्सपर्ट के मुताबिक रुपए की कीमत डिमांड और सप्लाई पर निर्भर होती है। किसी भी देश का विदेशी मुद्रा भंडार घटने बढ़ने के साथ ही उस देश की करेंसी की चाल बदलती रहती है। दरअसल ज्यादातर देशों का कारोबार डॉलर करेंसी में होता है। इसलिए अमेरिकी डॉलर को वैश्विक करेंसी का रुतबा हासिल है। चूकिं भारत भी अपना कारोबार डॉलर में ही करता है। ऐसे में डॉलर की कीमतें बदलने का असर भारतीय रुपए पर देखा जा सकता है।

रुपया मजबूत होने से लाभ

रुपए के मजूबत होने से कई क्षेत्रो को लाभ होता है जो इस तरह से हैं। कम होगी महंगाई – भारत बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करता है। अगर रुपए में मजबूती आती है तो इस क्षेत्र को फायदा होता है क्योंकि उन्हें क्रूड इंपोर्ट करने के लिए कम डॉलर चुकाना होगा। जिसके चलते कच्चे तेल के लिए भारत को कम चुकाना होगा। कच्चा तेल सस्ता होगा तो पेट्रोल ड़ीजल की कीमतें कम होंगी। पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने से महंगाई घटेगी। क्योंकि माल ढुलाई से लेकर यातायात का सबसे बड़ा साधन डीजल को ही माना जाता है।

किसानों को फायदा – रुपए के मजबूत होने से किसानों को भी फायदा है। दरअसल भारत बड़ी मात्रा में उर्वरक का आयात करता है। रुपए के मजबूत होने से यह सस्ता होगा। आयात करने वालों के लिए यह काम दाम में ज्यादा मिलेगा। जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा।

सस्ते होंगे इलेक्ट्रॉनिक समान – रुपया मजबूत होने से भारत सस्ते इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ज्यादा मात्रा में आयात कर सकेगा। जिससे इसकी कीमतों में असर देखने को मिलेगा। रुपए की मजबूती का सकारात्मक असर जेम्स एंड ज्वैलरी सेक्टर पर देखा जा सकेगा। इससे यह सस्ता होगा और आयात पर भी इसका असर आएगा।

डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे गिरकर 73.03 के स्तर पर बंद

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

घरेलू शेयर बाजार में कमजोरी और अमेरिकी मुद्रा की मजबूती के चलते बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे गिरकर 73.03 (अनंतिम) पर बंद हुआ। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया कमजोर रुख के साथ 73.10 के स्तर पर खुला और उतार-चढ़ाव भरे कारोबारी सत्र के अंत में 73.03 पर बंद हुआ, जो पिछले बंद भाव 72.87 से 16 पैसे की गिरावट के दर्शाता है। दिन के कारोबार में रुपए ने 72.90 के ऊपरी स्तर और 73.13 के निचले स्तर को देखा। इससे पहले मंगलवार को आरबीआई के नकदी बढ़ाने के उपायों के चलते रुपया 73 पैसे की मजबूती के साथ 72.87 पर बंद हुआ था। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.26 प्रतिशत बढ़कर 92.58 पर आ गया।

डीजीएफटी ने एन95 मास्क का निर्यात लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पेश की

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

एन95 मास्क के निर्यात का लाइसेंस केवल ऐसे निर्यातकों को देने पर विचार किया जाएगा जो सात से नौ सितंबर के बीच ऑनलाइन आवेदन करेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने सोमवार को इस संबंध में सूचना जारी की। मंत्रालय की सूचना के मुताबिक विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) एन95 या एफएफपी2 मास्क के निर्यात की अनुमति केवल उन्हीं निर्यातकों को देने पर विचार करेगा जो उपरोक्त तिथि में ऑनलाइन आवेदन करेंगे। यह निर्यात लाइसेंस पाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। हर महीने केवल 50 लाख मास्क के निर्यात को अनुमति दी जाएगी। अगस्त और सितंबर में कुल एक करोड़ एन95 या एफएफपी2 मास्क के निर्यात की अनुमति दी गयी थी।

फोन पर बात करने के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे, 27 प्रतिशत तक महंगे हो सकते हैं प्लान

नई दिल्ली। एजेंसी

मोबाइल यूजर्स के लिए टेलिकॉम सर्विसेज कम से कम 10 प्रतिशत तक महंगी हो सकती हैं। इंडस्ट्री अनुमान के मुताबिक अगले 7 महीनों में एयरटेल और वोडाफोन को अजस्ट किए गए ग्रॉस रेवेन्यू का 10 प्रतिशत देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को टेलिकॉम ऑपरेटर्स को 31 मार्च 2021 तक अजस्ट किए गए ग्रॉस रेवेन्यू का 10 प्रतिशत भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बाकी अमाउंट को 31 मार्च 2022 तक 10 किश्तों में देने का फैसला सुनाया है।

मार्च 2021 तक तक देने हैं 5000 करोड़ रुपये

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब मार्च 2021 तक एयरटेल को 2600 करोड़ और वोडाफोन-आइडिया को 5000 करोड़ रुपये देने होंगे। ऐसे में ब्रोकरेज फर्म वीगे के मुताबिक एयरटेल अपने ऐवरेज रेवेन्यू प्रति यूजर को 10 प्रतिशत और वोडाफोन 27 प्रतिशत तक बढ़ा सकती है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एयरटेल के लिए ARPU (प्रति यूजर औसत रेवेन्यू) 157 रुपये था, जबकि वोडाफोन-आइडिया के लिए यह 114 रुपये रहा।। जेफरीज ने कहा कि आने वाले समय में कंपनियां टैरिफ को एक बार और 10 प्रतिशत तक महंगा कर सकती हैं।

अगली तिमाही में महंगे हो सकते हैं टैरिफ

एंटरप्रेन्योर और टीएमटी अडवाइजर संजय कपूर ने कहा कि मंगलवार को आए फैसला टेलिकॉम कंपनियों द्वारास किए जाने वाले प्राइस हाइक से अलग है और इसने केवल भविष्य में ऐसा किए जाने की जरूरत पर जोर देने का काम किया है। कपूर ने आगे कहा, 'स्पेक्ट्रम कॉस्ट और दूसरे निवेशों को अगर अलग रख दिया जाए तो सर्विस प्रोवाइडर्स को डेटा यूसेज की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कम से कम 3-4 डॉलर प्रति यूजर औसत रेवेन्यू की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए अगली तिमाही तक टैरिफ रेट में जरूरी बढ़ोतरी हो सकती है।

'200 रुपये के प्रति यूजर औसत रेवेन्यू की पड़ेगी जरूरत'

टेलिकॉम ऑपरेटर्स ने चार सालों में पहली बार पिछले साल दिसंबर में प्लान्स को 40 प्रतिशत तक महंगा किया था। ऐसा करने के बाद साल 2020 की पहली छमाही में कंपनियों की कमाई में 20 प्रतिशत की बढ़त देखी गई। इस बारे में Analysys Mason के इंडिया और मिडिल ईस्ट हेड रोहम धमीजा ने कहा, 'हमें लगता है कि अगले 12-24 महीनों में टेलिकॉम कंपनियों को 200 रुपये के प्रति यूजर औसत रेवेन्यू की जरूरत पड़ेगी।'

पितृ दोष से पितृ मोक्ष की ओर आपकी आध्यात्मिक यात्रा

सत्संग ओर विवेक प्राणी के दो ये नेत्र हैं। जिसके पास ये दोनों नहीं हैं, वह मनुष्य अंधा है। जटाओं का भार और मृगचर्म से युक्त अनेक साधु वेशधारी दाम्भिक ज्ञानियों के रूप में इस संसार में भ्रमण करते लोग, लौकिक सुख में आशक्त, यत्र-तत्र, सर्वत्र यह कहते मिल जाएंगे- 'मैं ब्रह्म को जानता हूँ'। ऐसे कहने वाले अधिसंख्य कर्म तथा ब्रह्म दोनों से भ्रष्ट हैं। ऐसे ढोंगियों का परित्याग करना चाहिए। जो कर्म जीवात्मा को बंधन में नहीं ले जाता, वही सत्कर्म है। जो विद्या को मुक्ति प्रदान करती है, वही विद्या है। गृहस्थ भी सद्कर्मों द्वारा परिवार को ही तीर्थ मानकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तत्व का ज्ञान रखने वाले धर्मनिष्ठ होकर स्वर्ग जाते हैं।

यदि आरम्भ से ही मृत्यु को जीवन का अनिवार्य अतिथि मानकर चला जाएं, उसकी सुनिश्चिता को समझा जाए और अपनी दिनचर्या इस प्रकार बनाई जाये, जिससे मृत्यु के समय जीवन व्यर्थ जाने का पश्चाताप न रहे, तो मृत्यु हर किसी के लिए सरल और सुखद हो सकती है। मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति का चेहरा बहुत शांत और तनाव रहित दिखाई देता है तथा अनेकों का चेहरा विकृत हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि मृतक की आत्मा शांत या उद्विग्न अवस्था में बिदा हुई। अचानक मृत्यु किसी की नहीं होती। मृत्यु तीन क्रम में धीरे-धीरे होती है। इन तीनों क्रमों को स्लेनिकल, बायोलॉजिकल और सेलुलर कहा जाता है। प्रथम क्रम में स्लेनिकल मृत्यु वह है, जिसमें सांस, स्पंदन और मस्तिष्कीय विद्युत लहरों का प्रवाह रुक जाता है। इस स्तर पर मरे हुए व्यक्ति को हृदय की मालिश जैसे उपचारों द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है।

मृत्यु के दूसरे चरण में शरीर के कुछ भाग विसंगठित होते हुए भी इस दशा में बने रहते हैं कि विद्युत प्रवास के संचार से उनमें पुनः गतिशीलता उत्पन्न की जा सके तथा तीसरा और अंतिम मरण रोका जा सके। तीसरा सेलुलर मृत्यु वह है, जिसमें शरीर के कोष विगलन की स्थिति में पहुंच जाते हैं, फिर किसी भी स्थिति में जीवन की चेतना का वापस लौटना संभव नहीं होता। यदि मृतक को जीवन का अनिवार्य अतिथि मानकर चला जाए, तो निद्रा देवी की गोद में लम्बी थकान मिटाने के लिए जीवन की अनिवार्य घटना मृत्यु से घबराने तथा पश्चाताप करने का क्या औचित्य ?

साधना विधि

दीपक व अगरबत्ती जलाकर निम्न मंत्र का 108 बार जाप करें।

मंत्र – 'ऊँ श्रीं सर्व पितृ दोष निवारणाय् क्लेश हन हन सुख-शांति देहि-देहि फट स्वाहा।'

नित्य दूध से ने प्रसाद का भोग लगाएं और नित्य मंत्र जाप के बाद पश्चिम दिशा की तरफ वह भोग छत या मैदान में रख दें। इस प्रकार ग्यारह दिन तक प्रयोग करें, पितृ पक्ष के दरम्यान। बारहवें दिन उस मिट्टी के पात्र को किसी नदी या तालाब या पवित्र जलाशय में विसर्जित कर दें और वह लघु नारियल अपने घर में पूजा स्थल में रख दें। इस प्रयोग से पितृदोष से राहत मिलेगी और घर में सुख-शांति स्थापित हो जाती है।

पितृदोष निवारणार्थ साधनाएं

हमारे पूर्वजों, पितरों को जब तक मृत्यु के पश्चात् भी शांति नहीं मिलती, तब तक वे इसी लोक में भटकते रहते हैं। यदि हम उनके लिए श्राद्ध, कर्मकाण्ड आदि नहीं करेंगे तो उनको पुण्य लाभ नहीं होगा। ग्रहों की कुदृष्टि से भी पितृ दोष प्राप्त होता है। जन्म कुंडली का बारहवां (द्वादश भवन) भाव पितृदोष के लक्षण का आभास करवाता है। इसी भाव पर ग्रहों के अनुकूल तथा प्रतिकूल दृष्टियों से इस भाव द्वारा पितृ दोष का प्रभाव दृष्टांकित होता है। यदि द्वादश भवन में चन्द्रमा हो और उस पर मंगल की दृष्टि पड़ती हो तो जातक को पितृदोष होता है। मूल नक्षत्र में जन्में जातकों को पितरों का सत्कार, प्रसाद अनेक कष्टों द्वारा होता है। कुल पितृदोष ग्रस्त रहने पर पूर्वजों द्वारा पितृ ऋण न चुकाने पर बालक अपंग पैदा होते हैं। यदि राहु की महादशा में सूर्य की अन्तर्दशा में चन्द्र की प्रत्यन्तर दशा में पितृदोष होने पर व्यापक कष्ट उठाना पड़ता है।

पितृदोष – मुक्ति साधना

जब व्यक्ति अपने अंतिम समय में होता है तो एक क्षण ऐसा आता है जब वह तन्द्रा में चला जाता है और चित्रगुप्त के द्वारा उसके जीवन का सारा लेखा-जोखा उसकी आंखों के सामने चलचित्र की भांति तैर जाता है और जीवन में विभिन्न कर्मों के आधार पर वह व्यक्ति जीव अगले जीवन के लिए कर्म चयन करता है। ग्रंथों में कहा गया है कि' 'अन्ते या मतिः सा गतिः' अर्थात् अंत समय में जैसा विचार होता है, उसी हिसाब से व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। ऐसे समय में जीव का कोई सशक्त मार्ग दर्शक हो, तो उस आत्मा का शुभ-दायित्व निभा सकता है। आत्माएं, भौतिक वस्तुएं नहीं खाती, ये मात्र उनकी गंध (महक) ग्रहण करती हैं। ठीक उसी प्रकार वे आपकी बातों को सुनकर अच्छी या बुरी तरंगे ग्रहण कर अपनी दिव्य साधना तथा मंत्रों की तेजस्वी तरंगों से उसे सही सात्विक मार्ग-दर्शन देती हैं। यह व्यवस्था जब तक चलती है, जब तक उसे नवीन जन्म दिलवाने का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता तथा पूर्व जन्म की सभी स्मृतियां भुलाकर नये संस्कारों से युक्त कर देती हैं।

ये है साधना विधान

हमारे शास्त्रों में पितृदोष निवारण से संबंधित साधनाएं पितृ मुक्ति साधना कहलाती है। यह साधना श्राद्ध पक्ष में अपनी सुविधानुसार किसी भी दिन प्रातः काल सम्पन्न करें। यह एक दिवसीय साधना है और इसमें पितृ मुक्ति यंत्र दिव्य माला, प्रायण गुटिका की आवश्यकता होती है। साधक ब्रह्ममुहूर्त में उठे और सफेद धोती पहनकर दक्षिणाभिमुखी हो सफेद आसन पर बैठे। साधक को चाहिए कि अपने सफेद वस्त्र पर पितृ मुक्ति यंत्र स्थापित कर, उसके चारों ओर दिव्य माला को रखे। कुमकुम में दिवंगत व्यक्ति का नाम यंत्र पर लिखें। यदि साधना सभी पितरों के लिए हो तो सर्वपितृ लिखे यंत्र और माला का पूजन करें। यंत्र पर प्रायण गुटिका स्थापित करें और उसका पूजन भी करें।

श्रद्धा से किया गया दान ही श्राद्ध

ब्रह्मपुराण के अनुसार शास्त्रों में बताये गये नियम से श्रद्धा पूर्वक पितरों के उद्देश्य से ब्राह्मणों को दिया हुआ दान श्राद्ध कहलाता है। वहीं अन्य ग्रंथों के अनुसार मृत माता-पिता या पूर्वजों की तृप्ति के लिए श्रद्धा से किया गया अन्न, जल या किसी भी तरह का दान ही श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध का अधिकार पुत्र को है, लेकिन अगर पुत्र जीवित न हो तो पोते, पड़पोते या विधवा पत्नी भी श्राद्ध कर सकती है। पुत्र के न होने पर पत्नी का श्राद्ध पति भी कर सकता है।

ब्रह्मवैवर्त पुराणः देवकार्य से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है पितृकार्य

ब्रह्मपुराण के अनुसार विधि-विधान से श्राद्ध करने पर ब्रह्मा से लेकर सभी देवी-देवता और पितृ प्रसन्न होते हैं। नागरखण्ड के अनुसार श्राद्ध कर्म कभी व्यर्थ नही होता। ब्रह्मवैवर्तपुराण के अनुसार देवकार्य से भी ज्यादा महत्वपूर्ण पितृकार्य होता है। देवताओं से पहले पितरों को तृप्त करना चाहिए। श्राद्ध करने से कुल मे वीर, निरोगी, लंबी उम्र वाली और प्रसिद्धि पाने वाली संतान उत्पन्न होती हैं।

59 दिनों तक सभी शुभ कार्यों पर लगेगा ब्रेक

अश्विन माह इस बार 3 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक होगा। 59 दिनों की आश्विन माह की अवधि के बीच 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक अधिक मास रहेगा, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस महीने सूर्य संक्रांति नहीं होती, उसमें अधिक मास जुड़ जाता है। 32 माह 16 दिन 4 घंटे बीतने के बाद पुरुषोत्तम माह आता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार, हर दो साल बाद यानी तीसरे साल में अधिक मास जुड़ता है। सूर्य चंद्रमा की वार्षिक चाल में 11 दिनों के अंतर को इसका कारण बताया जाता है। सूर्य चंद्रमा के वर्षचक्र में 11 दिन का अंतर होता है, जिसे पाटने के लिए हर साल हर तीसरे वर्ष अधिक मास आता है। जानकार बताते हैं कि अधिक माह में शुभ कार्यों पर पाबंदी रहती है। जैसे प्रथम तीर्थ दर्शन, राज्याभिषेक, गृहप्रवेश, गृहारंभ, शादी-विवाह, जलाशयारामदेव प्रतिष्ठा आदि कार्य अधिक मास में वर्जित होते हैं। पुरुषोत्तम मास भगवान श्रीहरि विष्णु को समर्पित होता है। इसके अलावा अधिक मास के 33 देवताओं की पूजा का भी बहुत महत्व होता है। इस दौरान विष्णु, जिष्णु, महाविष्णु, हरि, कृष्ण, भधोक्षज, केशव, माधव, राम, अच्युत, पुरुषोत्तम, गोविंद, वामन, श्रीश, श्रीकांत, नारायण, मधुरिपु, अनिरुद्ध, त्रीविक्रम, वासुदेव, यगत्योनि, अनन्त, विश्वाक्षिभूणम्, शेषशायिन, संकर्षण, प्रद्युम्न, दैत्यारि, विश्वतोमुख, जनार्दन, धरावास, दामोदर, मघार्दन एवं श्रीपति जी की पूजा की जाती है, जिसका बहुत लाभ मिलता है।

भूलकर भी न करें पितृ पक्ष में ये गलतियां

हिन्दू पंचांग के अनुसार, इस साल का पितृ पक्ष 01 सितम्बर से शुरू होकर 17 सितम्बर 2020 तक चलेगा। इस साल पितृ पक्ष की कुल अवधि 17 दिनों की होगी। पितृ पक्ष एक महत्वपूर्ण पक्ष है। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 'पितर' देव स्वरूप होते हैं। पितृ पक्ष में श्राद्ध कर्म को पूर्ण किया जाता है। माता-पिता या किसी अन्य परिजन की मृत्यु के बाद उनकी संतृप्ति के लिए श्रद्धापूर्वक किए जाने वाले कर्म को पितृ श्राद्ध कहते है। ऐसी मान्यता है कि पितृ पक्ष में पूर्वज पृथ्वी पर होते हैं, इसलिए पितृपक्ष में उनका श्राद्ध करने से वे अपना आशीर्वाद हमको देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से सुख का द्वार खुलता है। पितरों को प्रसन्न करते वक्त यह ध्यान में रखें की कोई गलती न हो जाए जिससे पितर नाराज हो जाए।

पितृ पक्ष में भूलकर भी नहीं करना चाहिये ये 7 काम

- पितृ पक्ष में नया सामान नहीं खरीदना चाहिए।
- पितृ पक्ष में 15 दिन तक अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए।
- पितृ पक्ष में भिखारी को भीख देने से इनकार नहीं करना चाहिये। हिन्दू धर्म की मान्यता के अनुसार यह भी हो सकता है कि भिखारी के रूप में आपके पूर्वज आपके पास आए हों और भिक्षा देने से इनकार करना उनका अपमान करना होगा।
- पितृ पक्ष में पूजा के लिए लोहे के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
- जो व्यक्ति पितरों को तर्पण करते हैं उन्हें पितृ पक्ष के 15 दिनों तक किसी और के घर में खाना नहीं खाना चाहिए।

अगस्त में जम कर बिकीं कारें

मारुति की बिक्री 17% से ज्यादा बढ़ी

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) की बिक्री अगस्त में 17.1 प्रतिशत बढ़कर 1,24,624 इकाई पर पहुंच गई। एक साल पहले समान महीने में कंपनी ने 1,06,413 वाहन बेचे थे। कंपनी ने मंगलवार को बयान में कहा कि अगस्त में घरेलू बाजार में उसकी बिक्री 20.2 प्रतिशत बढ़कर 1,16,704 इकाई पर पहुंच गई, जो अगस्त, 2019 में 97,061 इकाई रही थी।

माह के दौरान कंपनी की मिनी कारों.. आल्टो और वैगन आर की बिक्री 94.7 प्रतिशत बढ़कर 19,709 इकाई पर पहुंच गई, जो अगस्त, 2019 में 10,123 इकाई थी। इसी तरह कॉम्पैक्ट खंड में स्विफ्ट, सेलेरियो, इग्निस, बलेनो और डिजायर की बिक्री 14.2 प्रतिशत बढ़कर 61,956 इकाई पर पहुंच गई, जो अगस्त, 2019 में 54,274 इकाई रही थी।

मध्यम आकार की सेडान सियाज की बिक्री 23.4 प्रतिशत घटकर 1,223 इकाई रह गई, जो एक साल पहले समान महीने में 1,596 इकाई थी। कंपनी के यूटिलिटी वाहनों विटारा ब्रेजा, एस-क्रॉस और एर्टिगा की बिक्री 13.5 प्रतिशत बढ़कर 21,030 इकाई पर पहुंच गई, जो अगस्त, 2019 में 18,522 इकाई रही थी। अगस्त में कंपनी का निर्यात 15.3 प्रतिशत घटकर 7,920 इकाई रह गया, जो एक साल पहले समान महीने में 9,352 इकाई रहा था।

अगस्त में एमजी मोटर इंडिया की खुदरा बिक्री 41.2 प्रतिशत बढ़ी

एमजी मोटर इंडिया की खुदरा बिक्री अगस्त में 41.2 प्रतिशत बढ़कर 2,851 इकाई पर पहुंच गई। पिछले साल समान महीने में कंपनी ने 2,018 वाहन बेचे थे। एमजी मोटर इंडिया ने कहा कि हाल में पेश हेक्टर प्लस को यात्रा पर अंकुशों में ढील के बाद परिवार खंड से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र भी आगे बढ़ रहा है। एमजी मोटर इंडिया के निदेशक बिक्री राकेश सिदाना ने कहा कि हमने जुलाई की तुलना में अगस्त में कुल उत्पादन बढ़ाया है। हम हेक्टर के पुराने ऑर्डरों को पूरा कर रहे हैं। साथ ही हमारा इरादा त्योहारी सीजन में वाहनों की डिलिवरी तेज करने का है।

MSME : लोन पर मिली मोहलत खत्म होने से 4 करोड़ फर्म्स पर मुसीबत

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

लोन मोरेटोरियम यानी आरबीआई की तरफ से दी गई लोन ईएमआई पर मोहलत खत्म हो चुकी है। इससे आम लोगों के साथ-साथ कारोबारियों के सामने भी पुनर्भुगतान की चुनौती सामने आ गई है। जिस सेक्टर के सामने चुनौती बड़ी है वो है एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग)। एमएसएमई, जो कि कोरोना संकट के पहले से ही आर्थिक दिक्कतों का सामना कर रहा है, सेक्टर में 4 करोड़ फर्म्स ऐसी हैं जिनके सामने वित्तीय मुसीबत आ गई है। ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के अलावा बाकी सेवा क्षेत्रों की फर्म्स अधिक संकट में हैं। असल में लॉकडाउन से ही सेवा क्षेत्र ठप्प है। इन फर्म्स के सामने कारोबार ठप्प पड़े रहने के कारण लोन चुकाना बहुत मुश्किल होगा। आने वाली स्थिति को देखते हुए बैंकों के एनपीए बढ़ने के संकेत दिए जा चुके हैं।

कितनी एमएसएमई पर है संकट

एमएसएमई मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस समय देश में 6.33 करोड़ एमएसएमई फर्म्स हैं। इन 6.33 करोड़ में से करीब 4.3 करोड़ से अधिक ट्रेड और दूसरे सर्विस सेक्टरों से ताल्लुक रखती हैं। एमएसएमई सेक्टर के संगठन लोन मोरेटोरियम बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सरकार से 6 महीनों का और समय मांगा गया है। मगर बैंकों की तरफ से फर्म्स को लोन चुकाने के लिए मैसेज भेजे जा रहे हैं।

जीडीपी आंकड़ों से सर्विस सेक्टर का संकट जाहिर

वे एमएसएमई जो सर्विस सेक्टर से जुड़ी हुई हैं उनकी खस्ता हालत का पता कल घोषित किए गए जीडीपी आंकड़ों से भी चलता है। सामने आए आंकड़ों से साफ जाहिर है कि होटल, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टरों के जीवीए में 47 फीसदी की भारी भरकम गिरावट आई है। सेवा क्षेत्र के कारोबारियों के अनुसार उनका व्यवसाय कोरोने से पहले लेवल पर नहीं पहुंचने तक वे इस स्थिति में नहीं होंगे कि लोन या फिर ब्याज अदा कर सकें। एक समस्या ये भी है कि अभी बहुत सी फर्म्स को कारोबार के लिए फंडिंग की जरूरत है। ऐसे में जिन्हें पहले से जरूरत है वे किसी भी तरह पिछला लोन अदा करने की स्थिति में नहीं होंगी।

सरकार 15 नये प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना कर रही है: गडकरी

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि देश को विनिर्माण गतिविधियों का बड़ा केन्द्र बनाने के प्रयास के तहत कुशल मानवशक्ति सृजित करने के वास्ते 15 नये प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं और 18 मौजूदा केन्द्रों का उन्नयन किया जा रहा है। गडकरी ने वीडियो कन्फ्रेंसिंग के जरिये राजस्थान के अलवर जिले में भिवाड़ी में एक प्रौद्योगिकी केन्द्र का उद्घाटन किया। गडकरी के पास राजमार्ग एवं सड़क मंत्रालय के साथ साथ सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) का भी प्रभार है। गडकरी ने प्रौद्योगिकी केन्द्रों का विस्तार करने के लिये राज्यों से जमीन और अन्य जरूरी सुविधायें और समर्थन उपलब्ध कराने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि ये विस्तार केन्द्र क्षेत्र के मौजूदा और नये उद्योगों की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा, "कुशल मानवबल तैयार करने के लिये हम 15 नये प्रौद्योगिकी केन्द्र बना रहे हैं और साथ ही 18 मौजूदा प्रौद्योगिकी केन्द्रों को उन्नत कर रहे हैं।" इस बीच एमएसएमई मंत्रालय के तहत आने वाले खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने सोमवार को कहा कि उसे भारतीय रेडक्रास सोसायटी से 10.5 लाख मास्क का अब तक का सबसे बड़ा आर्डर प्राप्त हुआ है। सोसायटी से उसे दूसरी बार यह आर्डर मिला है। एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने मास्क बनाकर सतत् रोजगार के अवसर पैदा करने के लिये सीवीआईसी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि चेहरे पर पहने जाने वाला मास्क जहां एक तरफ कोविड- 19 से बचने का सबसे प्रभावी उपाय है वहीं इनके उत्पादन से कारीगरों को बड़ी मात्रा में रोजगार भी उपलब्ध हुआ है।

रिलायंस रीटेल को मिल सकता है बड़ा निवेश, वॉलमार्ट के साथ डील के लिए चल रही बातचीत!

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

पिछले महीनों में रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स को तगड़ा निवेश हासिल हुआ है। अब मुकेश अंबनी रिलायंस रीटेल को लेकर बड़ी तैयारी में जुटे हैं। खबर ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में दिग्गज रीटेल कंपनी वॉलमार्ट निवेश कर सकती है। मुकेश अंबनी अब वॉलमार्ट को माइनोरिटी स्टेक बेचने की तैयारी कर रहे हैं। ऽदेहग्दु एदर्ह्लू के मुताबिक इस मामले की जानकारी रखने वाले एक शख्स ने कहा है कि इसे लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज और वॉलमार्ट के बीच बातचीत चल रही है। जानकारों की मानें तो मुकेश अंबानी की योजना रिलायंस रीटेल में वॉलमार्ट से निवेश लेकर अपने रीटेल कारोबार का विस्तार करने की है। अब वह सीधे तौर पर अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों को टक्कर देने की तैयारी में हैं। बता दें कि पिछले दिनों उन्होंने ऑनलाइन दवा बेचने वाली कंपनी नेटमेड्स का अधिकग्रहण कर के ई-फार्मेसी में तो सभी दिग्गज कंपनियों को टक्कर दे ही दी है, अब बाकी रीटोल कारोबार में भी वह सबसे लोहा लेने की तैयारी में हैं।

हाल ही में खरीदा है फ्यूचर ग्रुप का रीटेल बिजनेस

शनिवार को ही रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप के रीटेल बिजनेस को 24,713 करोड़ रुपयों में खरीद लिया है। यानी कि अब बिग बाजार रिलायंस का हुआ। रीटेल बिजनेस को लेकर मुकेश अंबानी कितनी बड़ी तैयारी में हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि पिछले ही दिनों उन्होंने 200 शहरों में जियोमार्ट की शुरुआत की है। अप्रैल के बाद से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जियो प्लेटफॉर्म यूनिट के लगभग 33% शेयर बेच दिए हैं और फेसबुक, गूगल जैसे निवेशकों से लगभग 1,52,056 करोड़ जुटाए हैं।

कब होगा अमेरिका का साथ व्यापार समझौता, गोयल ने बताया

नई दिल्ली (विप्र)। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (झ्ब्ल्प् उर्दब्ट) ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका के साथ शुरुआती व्यापार समझौता करने के लिए भारत तैयार है। गोयल ने कहा कि उन्होंने समझौते के समय के बारे में निर्णय अमेरिका के वाणिज्य मंत्री पर छोड़ा है। उन्होने यह भी कहा कि भारत समझौते पर अमेरिका के साथ लगातार बातचीत कर रहा है। गोयल ने कहा कि वह और अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) रॉबर्ट लाइटहाइजर ने शुरूआती व्यापार समझौते से संबद्ध लगभग सभी मसलों को सुलझा लिया है। उन्होंने कहा, 'मेरी हाल में ही व्यापार प्रतिनिधि लाइटहाइजर से बातचीत हुई है और हम दोनों इस बात पर सहमत हैं कि हम अमेरिकी चुनाव से पहले या उसके तुरंत बाद समझौता कर सकते हैं। पूरा पैकेज लगभग तैयार है और अगर अमेरिका में स्थानीय राजनीतिक स्थिति अनुमति दे तो किसी भी समय उसे अंतिम रूप दिया जा सकता है। जिस बात पर हमारी सहमति है, उस पर मैं कल समझौता करने के लिए तैयार हूं। मैंने इस बारे में निर्णय लेने की जिम्मेदारी बॉब (अमेरिका के वाणिज्य मंत्री विलबर रॉस) पर छोड़ दी है।'

बुनियादी उद्योगों में जुलाई में 9.6 प्रतिशत गिरावट, केवल उर्वरक उद्योग में दिखी वृद्धि

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

देश के आठ प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्र के उद्योगों में इस्पात एवं रिफाइनरी उत्पादन में आई भारी गिरावट के चलते जुलाई माह के दौरान कुल उत्पादन में 9.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। यह लगातार पांचवां महीना रहा है जब इस उद्योग क्षेत्र में गिरावट दर्ज की गई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सोमवार को जारी ओकड़ों के मुताबिक आठ प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्र के उद्योगों का उत्पादन इस साल जुलाई में 9.6 प्रतिशत घट गया जबकि एक साल पहले इसी माह में इसमें 2.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। उर्वरक क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी सात ढांचागत उद्योगों में जुलाई 2020 में गिरावट दर्ज की गई। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, इस्पात, सीमेंट और बिजली क्षेत्र में आलोच्य माह के दौरान गिरावट रही। केवल उर्वरक क्षेत्र ही ऐसा रहा जहां जुलाई माह के दौरान वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, इस समूचे क्षेत्र में अप्रैल माह के दौरान जहां 37.9 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई थी वहीं जुलाई में यह गिरावट कम होकर 9.6 प्रतिशत रह गई। जुलाई माह में एक साल पहले इसी माह के मुकाबले इस्पात क्षेत्र के उत्पादन में 16.5 प्रतिशत, रिफाइनरी उत्पादों में 13.9 प्रतिशत, सीमेंट में 13.5 प्रतिशत, प्राकृतिक गैस उत्पादन में 10.2 प्रतिशत, कोयला उत्पादन में 5.7 प्रतिशत, कच्चे तेल के उत्पादन में 4.9 प्रतिशत और बिजली उत्पादन में 2.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इसके विपरीत उर्वरक क्षेत्र के उत्पादन में जुलाई माह के दौरान 6.9 प्रतिशत की वृद्धि रही जबकि एक साल पहले जुलाई में इस क्षेत्र के उत्पादन में 1.5 प्रतिशत वृद्धि ही हुई थी। बुनियादी ढांचा क्षेत्र से जुड़े आठ प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में अप्रैल से जुलाई की अवधि की यदि बात की जाये तो क्षेत्र में एक साल पहले के मुकाबले उत्पादन में कुल मिलाकर 20.5 प्रतिशत की गिरावट रही है। पिछले साल इसी अवधि में क्षेत्र में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इक्रा लिमिटेड की प्रधान अर्थशास्त्री आदिति नायर ने बुनियादी उद्योग के आंकड़ों पर कहा मौजूदा उपलब्ध रुझान को देखते हुये वाहन उत्पादन और वस्तु निर्यात, "हमारा मानना है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में गिरावट जुलाई 2020 में कम होकर 7- 11 प्रतिशत रह जायेगी। एक महीना पहले जून में यह 16.6 प्रतिशत पर थी। औद्योगिक उत्पादान सूचकांक (आईआईपी) में बुनियादी ढांचा क्षेत्र के आठ प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों का 40.27 प्रतिशत योगदान है।

सरकार ने PUBG सहित 118 ऐप पर लगाया बैन

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

पबजी के दिवानों के लिए एक बुरी खबर है। केंद्र सरकार ने पबजी सहित 118 मोबाइल ऐप पर बैन लगा दिया है। केंद्र सरकार के इस कदम को भारत-चीन सीमा विवाद से जोड़ कर देखा जा रहा है। मालूम हो कि सूचना और प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्रालय ने पबजी सहित 118 मोबाइल ऐप पर देश में पूरी तरह से बैन कर दिया है। पबजी सहित 118 ऐप पर बैन का ऐलान आईटी मंत्रालय ने एक आदेश में किया है। जून में चीन-भारत के बीच हुए सीमा विवाद के बाद केंद्र सरकार ने चीन के 59 मोबाइल ऐप्प को बैन कर दिया था, जिनमें टिकटॉक और हेलो शामिल थीं।

और कौन से ऐप हुए बैन

आईटी मंत्रालय ने भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और

सार्वजनिक व्यवस्था के हित का हवाला देते हुए इन ऐप को बैन किया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार बैन की ऐप्स में बायडु, बायडु एक्सप्रेस वर्जन, टेनसेंट वॉचलिस्ट, फेसयू, वीचैट रीडिंग और टेनसेंट वीयून और पबजी मोबाइल लाइट शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा है कि ये ऐप भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रही गतिविधियों में लगी हुई हैं। मंत्रालय ने कहा कि विभिन्न स्रोतों से कई शिकायतें मिली हैं, जिनमें अनधिकृत तरीके से उपयोगकर्ताओं के डेटा की ट्रांसमिटिंग शामिल है।

करोड़ों भारतीय को होगा फायदा

मंत्रालय ने ये भी कहा है कि यह कदम करोड़ों भारतीय मोबाइल और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा करेगा। यह निर्णय भारतीय साइबर स्पेस की सुरक्षा, सिक्योरिटी और संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए एक लक्षित कदम है। भारत सरकार ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब चीन ने पैंगोंग त्सो के दक्षिणी तट के पास घुसपैठ का प्रयास किया, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। इस साल जून में भारत ने चीनी लिंक वाली 59 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसमें टिकटोक, यूसी ब्राउज़र, वीबो, बायडु मैप और बायडु ट्रांसलेशन शामिल हैं। तब भी सरकार ने देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा का हवाला दिया था।

दुरुपयोग की भी रिपोर्ट्स

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को विभिन्न स्रोतों से कई शिकायतें मिलीं, जिनमें एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप के दुरुपयोग के बारे में आईं रिपोर्ट भी शामिल हैं। शिकायतें कथित रूप से उपयोगकर्ताओं के डेटा चोरी और सर्वर को अनधिकृत तरीके से ट्रांसमिटिंग की हैं, जो संभवतः भारत के बाहर की लोकेशन पर हैं। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने भी इन विवादास्पद ऐप्स को बैन करने के लिए एक सिफारिश भेजी।

अब शहरी इलाकों में भी मिलेगा मनरेगा का काम, इन शहरों से होगी शुरुआत

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण शहरों में लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसे देखते हुए सरकार अब मनरेगा को शहरों में भी शुरू करने पर विचार कर रही है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव संजय कुमार के मुताबिक अगर इस प्रोग्राम को मंजूरी मिलती है तो इसे छोटे शहरों में शुरू किया जा सकता है और इसका शुरुआती बजट 35,000 करोड़ रुपये हो सकता है। उन्होंने कहा, सरकार पिछले साल से इस पर विचार कर रही है। कोविड-19 महामारी ने इस पर चर्चा की प्रक्रिया तेज कर दी है।

सरकार पहले ही इस साल मनरेगा पर 1 लाख करोड़ रुपये

से अधिक खर्च कर रही है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिन का काम और 202 रुपये की न्यूनतम दिहाड़ी दी जाती है। अगर इसे शहरों में लागू किया जाता है तो इससे कोरोना वायरस के कारण सबसे अधिक प्रभावित हुए लोगों को कुछ राहत मिलेगी। इस महामारी के कारण देश की इकॉनमी बुरी तरह प्रभावित हुई है और चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में 23.9 फीसदी की रेकॉर्ड तिमाही गिरावट आई है।

छोटे शहरों में शुरुआत

कुमार ने कहा कि मनरेगा के शहरी संस्करण को छोटे शहरों में लागू करने की योजना है क्योंकि अमूमन बड़े शहरों की परियोजनाओं को पेशेवर विशेषज्ञता की जरूरत पड़ती है। मनरेगा के तहत ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण, कुएं की खुदाई और वनीकरण जैसे काम कराए जाते हैं। अब इसके दायरे में 27 करोड़ से अधिक लोग हैं और लॉकडाउन के बीच शहरों से लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने में इसकी अहम भूमिका रही है।

कितने हैं बेरोजगार

लंदन स्कूल ऑफ इकॉनमिक्स के एक विश्लेषण के मुताबिक कोविड-19 के कारण शहरों में लाखों लोगों की आजीविका खत्म हो गई है जिससे उनके सामने रोजीरोटी का संकट खड़ा हो गया है। सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकॉनमी (CMIE) के मुताबिक अप्रैल में 12.1 करोड़ से अधिक लोगों का रोजगार खत्म हो गया जिससे बेरोजगारी दर 23 फीसदी के रेकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। लेकिन आर्थिक गतिविधियों के शुरू होने के बाद इसमें गिरावट आई है।

अब नहीं छपेंगे सरकारी कैलेंडर और डायरी, सरकार ने जारी किया आदेश

नई दिल्ली। एजेंसी

कोरोना काल में सरकार अपने खर्चों में कटौती करने में लगी है। इसी सिलसिले में अब सरकार ने अब सरकारी प्रिंटिंग गतिविधियों को बंद करने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि अब विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, सरकारी कंपनियों और बैंकों द्वारा फिजिकल फॉर्मेट में कैलेंडर, डायरी, शेड्यूलर और दूसरी सामग्री की प्रिंटिंग नहीं होगी। अब यह सामग्री डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध होगी।

वित्त मंत्रालय ने आज एक बयान में कहा कि दुनिया तेजी से डिजिटल तरीकों को अपना रही है और भारत सरकार ने भी बेस्ट प्रैक्टिस को अपनाने का फैसला किया है। कॉफी टेबल बुक्स की प्रिंटिंग भी नहीं होगी और ई-बुक्स के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि सभी संबंधित विभागों को इन गतिविधियों के लिए डिजिटल और ऑनलाइन तरीकों को अपनाना चाहिए और इसके लिए नए तरीके खोजने का प्रयास करना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि कोरोना संकट के कारण देश की इकॉनमी बुरी तरह प्रभावित हुई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में 23.9 फीसदी की रेकॉर्ड गिरावट आई है। साथ ही सरकार का जीएसटी कलेक्शन भी अगस्त में पिछले साल की तुलना में 12 फीसदी कम रहा है। इस साल राजकोषीय घाटे के भी लक्ष्य से दोगुना रहने की आशंका है। यही वजह है कि सरकार अपने खर्चों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है।

इनोवेशन रैंकिग में भारत पहली बार टॉप 50 में, मध्य और दक्षिण एशिया में नंबर वन

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

इनोवेशन के मामले में पिछले कुछ वर्षों में भारत की स्थिति में लगातार सुधार आ रहा है। इस साल के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII 2020) में भारत 4 स्थान के सुधार के साथ 48वें स्थान पर पहुंच गया है। दिलचस्प बात यह है कि मध्य और दक्षिण एशिया में भारत पहले स्थान पर है। 2015 में भारत ग्लोबल इंडेक्स में 81वें नंबर पर था। 2016 में वह 66वें, 2017 में 60वें, 2018 में 57वें और 2019 में 52वें स्थान पर था। इस सूची में स्विट्जरलैंड ने अपनी टॉप रैंकिंग बरकरार रखी है। इसी तरह स्वीडन दूसरे और अमेरिका तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। ब्रिटेन एक स्थान के सुधान के साथ चौथे स्थान पर आ गया है जबकि नीदरलैंड्स एक स्थान फिसलकर पांचवें पर चला गया है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने पहली बार टॉप 10 में जगह बनाई है। वह टॉप 10 में जगह पाने वाला दूसरा एशियाई देश है। सिंगापुर इस सूची में 8वें स्थान पर है। छठे नंबर पर डेनमार्क, सातवें पर फिनलैंड और नौवें नंबर पर जर्मनी है।

क्या हैं भारत की सफलता का राज

इस सूची में भारत के अलावा चीन, फिलीपींस और वियतनाम ने हाल के वर्षों में अच्छा प्रदर्शन किया है। चीन 14वें स्थान पर है। मध्य और दक्षिण एशिया में भारत ने अपनी टॉप रैंकिंग बरकरार रखी है। इस इलाके में ईरान दूसरे और कजाकस्तान तीसरे स्थान पर है। गरीब देशों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा इनोवेटिव इकॉनमी है।

भारत ने जीआईआई के सभी इंडिकेटरों में अपनी स्थिति में सुधार किया है। आईसीटी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑनलाइन सर्विसेज, साइंस और इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट्स की संख्या और आरएंडडी इंटेंसिव ग्लोबल कंपनीज जैसे इंडिकेटरों में भारत टॉप 15 में है। आईआईटी बंबई और दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलूरु जैसे संस्थानों और टॉप साइंटिफिक पब्लिकेशंस के दम पर भारत ने यह मुकाम हासिल किया है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित । संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।